भूपिंदर सिंह

बनाम

चंडीगढ़ का संघ क्षेत्र

(2008 आपराधिक अपील सं. 1047)

10 जुलाई, 2008

[डॉ. अरिजीत पसायत और पी. सदाशिवम्, जे.जे.]

दंड संहिता, 1860-धारा 375 खंड 'चतुर्थ' और 376 – बलात्कार- अभियुक्त द्वारा पहली शादी के तथ्य को छिपाते हुए दूसरी शादी - दूसरी पत्नी द्वारा शिकायत – विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्धी और 7 वर्ष के कठोर कारावास का दण्ड – उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धी की पुष्टि की किन्तु इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दूसरी पत्नी को अभियुक्त की पहली शादी की जानकारी थी, सजा को कम करते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास दिया - 1,00,000/- रूपये की क्षतिपूर्ति स्वीकृत – अपील में यह अभिनिर्धारित किया गया कि दोषसिद्धि न्यायोचित-मामला धारा 375 के खंड 'चौथे' के तहत आता है। शिकायत दर्ज करने में हुई देरी का तथ्य अपराध को खत्म नहीं कर सकता - दोषसिद्धी और क्षतिपूर्ति में हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं।

अपीलार्थी-अभियुक्त के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी कि उसने इस तथ्य को छिपाते हुए कि वह एक शादीशुदा आदमी था, शिकायतकर्ता से शादी की। वे पति-पत्नी के रूप में रहते थे। शिकायतकर्ता गर्भवती भी हो गई। उसकी शादी के 4 साल बाद उसे पता चला कि आरोपी पहले से ही शादीशुदा था। लगभग एक महीने बाद, उसने एक लड़की को जन्म दिया। उसने एक शिकायत दायर की और प्रकरण अन्तर्गत धारा 420/376/498 ए – भारतीय दण्ड संहिता दर्ज करवाया गया। अभियुक्त ने दलील दी कि

शिकायतकर्ता को जानकारी थी कि वह पहले से ही शादीशुदा था। निचली अदालत ने उसे अन्तर्गत धारा 376 और 417 भारतीय दण्ड संहिता में दोषी ठहराया और उसे 7 साल के कठोर करावास और 10,000 रूपये जुर्माना डिफॉल्ट खण्ड के साथ सजा सुनाई। उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धी की पुष्टि की तथा यह अभिनिर्धारित किया कि मामला धारा 375 भारतीय दण्ड संहिता के खण्ड 'चतुर्थ' के तहत आता है। मगर इस तथ्य को देखते हुए कि शिकायतकर्ता ने, यह जानते हुए कि अभियुक्त शादीशुदा है स्वयं को अभियुक्त को समर्पित किया, कारावास की सजा को कम करते हुए 3 वर्ष तक के कठोर कारावास एवं 1,00,000/- रूपये की क्षतिपूर्ति शिकायतकर्ता को अदा करने का आदेश दिया अतः अभियुक्त की ओर से तथा शिकायतकर्ता की और से प्रस्तुत अपीलें खारिज की जाती है।

अभिनिर्धारित : 1.1. यह कहना सही नहीं है कि जब शिकायतकर्ता को पता था कि वह एक विवाहित पुरुष है, धारा 375 भारतीय दण्ड संहिता खंड "चौथा" लागू नहीं होता है। हालांकि, शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उसने आरोपी से शादी कर ली है, यह तथ्य कई दस्तावेजों से स्थापित होता है, लेकिन जहां तक आरोपी-अपीलकर्ता का सवाल है, इससे उसके सम्बन्ध में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चूंकि, वह पहले से ही शादीशुदा था, इसलिए बाद की शादी, यदि कोई की हो, की कानून में कोई मान्यता नहीं है और वह शुरू से ही शून्य प्रभावी है। किसी भी स्थिति में, आरोपी-अपीलकर्ता कानूनी तौर पर शिकायतकर्ता से शादी नहीं कर सकता था। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375 के खंड "चौथा" को पढ़ने से यह स्थिति स्पष्ट हो जाती है। [पैरा 11]

1.2. शिकायतकर्ता को मामले की जानकारी तारीख 06-03-1994 से है, लेकिन पहली सूचना रिपोर्ट 19-09-1994 को दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि 16-04-1994 को घटना के बारे में जानने के तुरंत बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया

और इसलिए, पहले शिकायत दर्ज करने की स्थिति में नहीं थी। उनके अनुसार आरोपी-अपीलकर्ता की शादी के बारे में जानकर वह पूरी तरह से सदमे में थी। हालांकि स्पष्टीकरण वास्तव में संतोषजनक नहीं है, लेकिन कानून की स्थिति को देखते हुए कि आरोपी वास्तव में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी था, शिकायतकर्ता द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाने में किया गया विलम्ब किसी भी स्थिति में, अपराध को खत्म नहीं कर सकता है। [पैरा 11]

2. उच्च न्यायालय ने मामले के विशिष्ठ तथ्यों, खासकर शिकायतकर्ता को आरोपी के शादीशुदा होने के बारे में जानकारी को ध्यान में रखते हुए सजा कम कर दी है। उच्च न्यायालय ने सजा कम करने और 1,00,000/- रूपये का मुआवजा देने के पर्याप्त और पर्याप्त कारण बताए हैं। उच्च न्यायालय द्वारा बताए गए कारणों में कोई त्रुटि नहीं है। [पैरा 12]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः 2008 की आपराधिक अपील सं. 1047

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ द्वारा आपराधिक अपील सं. 698-एसबी/1999 में पारित अंतिम निर्णय दिनांक 06-09-2006 से।

के साथ

2008 की आपराधिक अपील संख्या 1048

जसबीर सिंह मलिक, आर. के. त्रिपाठी, पी. के. सिंह, धरम बीर, राज वोहरा, जसप्रित गोगिया और विपिन गोगिया, अपीलार्थी की ओर से।

अजय पाल, प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था-

डॉ. अरिजीत पसायत, जे.,

1. पक्षों के विद्वान् वकील को सुना।

2. अनुमति प्रदान की गई।

3. हालांकि 2006 की एस.एल.पी. (सी.आर.एल.) संख्या 6796 में, नोटिस जारी नहीं किया गया है, पक्षकारों के अनुरोध पर और उनकी सहमति से, इसे 2007 की एस.एल.पी. (सी.आर.एल.) संख्या 1411 के साथ लिया गया था। जहां नोटिस जारी किया गया था।

4. इन अपीलों में आपराधिक अपील संख्या 698 एस.बी./1999 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को चुनौती दी गई है। अपीलकर्ता-भूपिंदर सिंह (बाद में "अभियुक्त" के रूप में संदर्भित) ने विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, चंडीगढ द्वारा पारित दिनांक 20-09-1999 के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की थी, जिसमें उसे धारा 376 और 417 के भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में संहिता) तहत दडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। उसे पहले अपराध के लिए सात साल के कठोर कारावास और डिफॉल्ट शर्तों के साथ 10,000/- रूपये का जुर्माना भरने और दूसरे अपराध के संबंध में नौ महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी।

5. अभियोजन पक्ष का मामला, जैसा कि मुकदमे के दौरान सामने आया, इस प्रकार हैः

शिकायतकर्ता मंजीत कौर ने शिकायत दर्ज कराई कि वह ऑल बैंक एम्प्लॉइज अर्बन सैलरी अर्नर्स थ्रिफट क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड में क्लर्क के पद पर कार्यरत थी और सितंबर, 1991 तक इस पद पर कार्यरत थी। वह रोजाना नारायणगढ जिला अंबाला

से आती-जाती थी, जहां उसकी बहन रहती थी। आरोपी-भूपिंदर सिंह स्टेट बैंक आफ पटियाला, सेक्टर 17-सी, चंडीगढ में डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में कार्यरत था। वह उसके आफिस में आता था और नजदीकियां बढाता था और फिर खुद को अविवाहित बता कर उससे शादी करने के लिए कहता था। आरोपी-भूपिंदर सिंह ने उस पर जल्द से जल्द एक साधारण समारोह के माध्यम से गुरूद्वारे में शादी करने का दबाव डाला और कहा कि बाद में माता-पिता से अनुमति ली जा सकती है और उसके बाद शादी बहुत धूमधाम से की जाएगी। फिर वह आरोपी के प्रस्ताव पर राजी हो गई फिर 04-12-1990 को, मंजीत कौर और भूपिंदर सिंह ने पवित्र ग्रंथ साहिब के सामने माला का आदान-प्रदान करने के बाद गुरूद्वारे में अपनी शादी संपन्न की। उस समय उसकी चचेरी बहन जोगिंदर कौर का पति सोहन सिंह भी मौजूद था, फिर वह आरोपी के साथ मकान नम्बर 3166, सेक्टर 22-सी (टॉप फलोर), चंडीगढ में रहने लगी, जहां आरोपी उसी बैंक में काम करने वाले जे.पी. गोयल के साथ संयुक्त रूप से रह रहा था। फिर वे 27-12-1990 को हनीमून के लिए कसौली गए और एक होटल में रूके। फिर उसका आफिस सेक्टर 17 से सेक्टर 42, चंडीगढ में स्थानांतरित हो गया। वह और आरोपी मकान नम्बर 1110, सेक्टर 42-बी, चंडीगढ में स्थानांतरित हो गए और किसी प्रीतम सिंह के स्वामित्व वाले किराए के आवास में रहने लगे। मकान मालिक ने पुलिस स्टेशन, सेक्टर 36, चंडीगढ में उन्हें पति-पत्नी के रूप में दिखाते हुए एक सूचना भी प्रस्तुत की थी और इससे पहले भूपिंदर सिंह द्वारा विधिवत एक फार्म भरा गया था और स्वयं को उसका पति होने के तथ्य को स्थापित करने के लिए मकान मालिक को सौंपा। आरोपी ने मई 1991 में पंचकुला की एक सोसायटी से 5,000/- रूपये का ऋण भी लिया था, जहां उसने उसे अपनी पत्नी के रूप में नामित किया था। वह गर्भवती हो गईं, लेकिन आरोपी ने उसकी इच्छा के विरूद्व कौशल नर्सिंग होम से उसका गर्भपात करा दिया।

आरोपियों के दबाव में उसने सितंबर 1991 में नौकरी छोड दी थी। वर्ष 1992 में, आरोपी- भूपिंदर सिंह को चंडीगढ से रोपड स्थानांतरित कर दिया गया और वे रोपड में स्थानांतरित हो गए और मकान नम्बर 111, स्ट्रीट नंबर 8, मल्होत्रा कॉलोनी, रोपड में रहने लगे। वे फिर से चंडीगढ वापस आ गए और मकान नंबर 859, सेक्टर 38, चंडीगढ में रहने लगे और आरोपी- भूपिंदर सिंह रोजाना चंडीगढ से रोपड जाने लगा। उन्हें मई 1993 में पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ में दैनिक वेतन पर क्लर्क के रूप में पुनः रोजगार मिला और उन्होंने एच.एन.ओ. का दौरा किया। सी-146, सेक्टर 14, पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ, 1993 में दिवाली की पूर्व संध्या पर। जुलाई 1993 में वह फिर से गर्भवती हो गईं और मार्च, 1994 तक उनके संबंध मधुर रहे। दिनांक 06-03-1994 को जब वह रोज गार्डन गईं थी, तो उसकी मुलाकात देविंदर कुमार बंसल और विनोद शर्मा से हुई, जो उसके पति भूपिंदर सिंह के दोस्त थे। उन लोगों ने उसे बताया कि आरोपी भूपिंदर सिंह पहले से ही गुरिंदर कौर नाम की लडकी के साथ शादीशुदा है और उस शादी से उसके बच्चे भी हैं। उसने उनसे पूछा कि उन्होंने उसे उसके पति की पिछली शादी के बारे में क्यों नहीं बताया। लेकिन वे जवाब देने से बचते रहे, यह जानकर वह हैरान रह गईं और आवास पर पहुंचने के बाद, उसने भूपिंदर सिंह के बारे में पूछा, जो उसी दिन कुछ प्रशिक्षण पाठयक्रम में भाग लेने के बहाने पटियाला के लिए निकला था और दिनांक 13-03-1994 तक वापस नहीं लौटा। वह आरोपी भूपिंदर सिंह का पता जानने के लिए देविंदर बंसल के घर गईं और वहां भूपिंदर सिंह अपनी पत्नी गुरिंदर कौर के साथ आया और झगडा करने लगा और फिर मंजीत कौर ने पुलिस को सूचित करने की कोशिश की। लेकिन भूपिंदर सिंह की बहन का पति दलजीत उसे ले आया और उसके घर में छोड दिया। 16-04-1994 को, उसे जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसने एक बेटी को जन्म दिया। उसने भूपिंदर सिंह को इस बारे में सूचित किया

क्योंकि वह बच्चे का पिता था लेकिन भूपिंदर सिंह नहीं आया। उसकी शिकायत पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 420, 376, 498ए के तहत दंडनीय अपराध के लिए मामला दर्ज किया गया था। इसकी जाँच की गई। जाँच अधिकारी ने जाँच के दौरान आरोपी- भूपिंदर सिंह और अभियोजक मनजीत कौर को पति-पत्नी के रूप में दिखाने वाले कई दस्तावेज एकत्र किए। जाँच के बाद चालान पेश किया गया। अभियुक्त-अपीलकर्ता को मुकदमे का सामना करना पडा। मुकदमे के बाद उसे दोषी ठहराया गया और उपरोक्त के अनुसार सजा सुनाई गई। उसने हाई कोर्ट में अपील दायर की। शिकायतकर्ता की और से सजा बढाने के लिए आपराधिक निगरानी दायर की गई थी।। इसके अलावा एक सी.आर.एल. विविध दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 357 के तहत मुआवजा देने के लिए भी आवेदन दायर किया गया था।

6. उच्च न्यायालय ने गवाहों, विशेष रूप से, चंडीगढ के जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार, हरवर्धन (पी.डब्ल्यू.2) की साक्ष्य का उल्लेख किया, जिसमें यह दर्ज किया गया था कि शिकायतकर्ता मंजीत कौर ने 16-04-1994 को जनरल अस्पताल, सेक्टर-16, चंडीगढ में सामान्य रूप से एक लडकी को जन्म दिया था। जहाँ आरोपी-अपीलकर्ता का नाम पिता के रूप में उल्लेखित था। माल सिंह (पी.डब्ल्यू.-10) की साक्ष्य का भी संदर्भ दिया गया था जिसके घर में अपीलकर्ता और शिकायतकर्ता रहते थे। `संहिता` की धारा 313 के तहत अपने बयान में अपीलकर्ता ने यह बचाव लिया कि उसने गुरिंदर कौर के साथ शादी के बाद अपीलकर्ता को जानना शुरू किया। शिकायतकर्ता उसकी पत्नी को उसके साथ शादी से पहले से जानती थी और वह अपनी मां के साथ 1988 में सेक्टर 23, चंडीगढ में उनके घर आई थीं, जहां उसकी मां ने उससे नौकरी दिलाने का अनुरोध किया था क्योकि वह पढाई पूरी कर चुकी थी और नौकरी करना चाहती थी। शिकायतकर्ता छह महीने तक उनके घर में रही। इसके बाद उन्होंने उसके लिए नौकरी

की व्यवस्था की। हालांकि, वह बदल गई थी और चरित्रहीन स्वभाव की होने के कारण उसने कई लोगों का मनोरंजन किया। जब उसे पता चला कि वह चरित्रहीन है और विषम समय में अलग-अलग व्यक्तियों के साथ बाहर जा रही है, तो उसने आपत्ति जताई और शिकायतकर्ता को अपने तरीके सुधरने के लिए कहा। लेकिन उसने उससे लडना शुरू कर दिया और पैसे की मांग की जो उसने नहीं दिया और बच्चे को जन्म देने के बाद उसने झूठी शिकायत दर्ज कराई। गुरिंदर कौर (पी.डब्ल्यू.-20) ने कहा कि वह शिकायतकर्ता को उसकी शादी से पहले से जानती थी। यह दिखाने के लिए दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए कि सरकारी दस्तावेजों में, आरोपी-अपीलकर्ता ने शिकायतकर्ता को अपनी पत्नी और नामंकित व्यक्ति के रूप में दिखाया था।

7. उच्च न्यायालय ने पाया कि मौजूदा मामला भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375 के खंड "चौथे" के अन्तर्गत आता है और इसलिए, वह अपराध का दोषी था और धारा 376 भारतीय दण्ड संहिता के तहत सजा के लिए उत्तरदायी था। तदनुसार, जैसा कि निर्णित किया गया था, दोषसिद्वि को बरकरार रखा गया। लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि शिकायतकर्ता को उसकी शादी के बारे में पता था, और फिर भी उसने संभोग के लिए उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, इसे सजा कम करने और पर्याप्त मुआवजा देने के लिए एक उपयुक्त मामला माना गया। तदनुसार, विचारण न्यायालय द्वारा दिये गये सात साल के कठोर कारावास के स्थान पर तीन साल के कठोर कारावास की सजा दी गई। मुआवजा 1,00,000/- रूपये तय किया गया था जिसे तीन महीने के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। यह भी निर्देशित किया गया था कि मुआवजे की राशि का भुगतान नहीं करने की स्थिति में सजा में कटौती प्रभावी नहीं होगी।

8. अभियुक्त-अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जब शिकायतकर्ता को पता था कि वह एक विववाहित व्यक्ति है और फिर भी उसके साथ संभोग के लिए सहमति दी है, तो धारा 375 भारतीय दण्ड संहिता के खंड "चौथे" का प्रावधान लागू नहीं होगा। यह भी तर्क दिया गया कि यह तथ्य कि शिकायतकर्ता को उसके विवाहित पुरूष होने के बारे में पता था, उसके द्वारा दायर मुकदमे में किए गए कथनों से स्पष्ट रूप से स्थापित होता है, जहां उसने यह घोषणा करने की मांग की थी कि वह आरोपी की पत्नी है। अधिरोपित गई सजा को कठोर बताया है। हालांकि, यह बताया गया कि उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मुआवजे को शिकायतकर्ता द्वारा जमा कर दिया गया है और शिकायतकर्ता द्वारा ले लिया गया है।

9. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यह एक स्पष्ट मामला है जहां भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375 का खंड "चौथा" लागू होता है। शिकायतकर्ता के विद्वान वकील ने कहा कि यह एक ऐसा मामला है जहां सजा में कोई कमी करना अनावश्यक है। उच्च न्यायालय इस गलत धारणा पर आगे बढा कि शिकायतकर्ता को पता था कि आरोपी एक विवाहित व्यक्ति था। यह भी तर्क दिया गया कि दिया गया मुआवजा अत्यंत कम है।

10. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375 का खंड "चौथा" इस प्रकार है

> "375 बलात्कार- एक पुरूष को "बलात्कार" करने वाला कहा जाता है, जो इसके बाद छोडे गए मामले को छोड कर, निम्नलिखित छह विवरणों में से किसी एक के अंतर्गत आने वाली परिस्थितियों में एक महिला के साथ संभोग करता है -
>
> XXX XXX XXX

चौथा - उसकी सहमति से, जब पुरूष जानता है कि वह उसका पति नहीं है, और उसकी सहमति इसलिए दी गई है क्योकि वह मानती है कि वह एक और पुरूष है जिससे वह है या खुद को कानूनी रूप से विवाहित मानती है।

XXX XXX XXX"

11. हालांकि कुछ हद बल देते हुए यह आग्रह किया गया है कि जब शिकायतकर्ता को पता था कि वह एक विवाहित व्यक्ति था, तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375 के खंड "चौथे" का कोई उपयोग नहीं होता है, यह रूख स्पष्ट रूप से बिना किसी आधार के है। हालांकि, शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उसने आरोपी से शादी कर ली है, यह तथ्य कई दस्तावेजों से स्थापित होता है, लेकिन जहां तक आरोपी-अपीलकर्ता का सवाल है, इससे उसके सम्बन्ध में कोई प्रभाव नहीं पडता। चूंकि, वह पहले से ही शादीशुदा था, इसलिए बाद की शादी, यदि कोई की हो, की कानून में कोई मान्यता नहीं है और वह शुरू से ही शून्य प्रभावी है। किसी भी स्थिति में, आरोपी-अपीलकर्ता कानूनी तौर पर शिकायतकर्ता से शादी नहीं कर सकता था। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375 के खंड "चौथे" को पढने से यह स्थिति स्पष्ट हो जाती है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि शिकायतकर्ता द्वारा दावा की गई जानकारी की तारीख 06-03-1994 है, लेकिन पहली सूचना रिपोर्ट 19-09-1994 को दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि 16-04-1994 को घटना के बारे में जानने के तुरंत बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया और इसलिए, पहले शिकायत दर्ज करने की स्थिति में नहीं थी। उनके अनुसार आरोपी-अपीलकर्ता की शादी के बारे में जानकर वह पूरी तरह से सदमे में थी। हालांकि स्पष्टीकरण वास्तव में संतोषजनक नहीं है, लेकिन कानून की स्थिति को देखते हुए कि आरोपी वास्तव में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375 के

तहत दंडनीय अपराध का दोषी था, शिकायतकर्ता द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाने में किया गया विलम्ब किसी भी स्थिति में, अपराध को खत्म नहीं कर सकता है।

12. अभियुक्त द्वारा दायर अपील खारिज की जाती है। हाई कोर्ट ने मामले के विशिष्ठ तथ्यों, खासकर शिकायतकर्ता को आरोपी के शादीशुदा होने के बारे में जानकारी को ध्यान में रखते हुए सजा कम कर दी है। उच्च न्यायालय ने सजा कम करने और 1,00,000/- रूपये का मुआवजा देने के पर्याप्त कारण बताए हैं। उच्च न्यायालय द्वारा बताए गए कारणों में कोई त्रुटि नहीं है और इसलिए, शिकायतकर्ता द्वारा दायर अपील निराधार है और खारिज की जाती है। तदनुसार, दोनों अपीलें खारिज की जाती हैं।

के.के.टी.

अपीलें खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अनिता सिंदल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।